

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1272/2016/अलवर

अपील संख्या 1273/2016/अलवर

अपील संख्या 1274/2016/अलवर

अपील संख्या 1275/2016/अलवर

मैसर्स बीम ग्लोबल स्प्रिट्स एण्ड वाईन (इण्डिया) प्रा.लि.,  
गांव कारोड़ा, बहरोड़, जिला अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम्  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया,  
अधिकृत अभिभाषक  
श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "सीएसटी अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "आरवेट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, एवं 61 के अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 03.05.2016 के विरुद्ध आरवेट अधिनियम की धारा 83 सपठित सीएसटी अधिनियम की धारा 18ए के अन्तर्गत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।
2. उपरोक्त चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही पक्षकार से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारी द्वारा IMFL का विनिर्माण कर राज्यान्तर्गत व अन्तर्राज्यीय विक्रय, राज्य में स्थित CSD कैंटीन को विक्रय तथा स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है। उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 06.01.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी द्वारा किया गया। व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विवरण की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि में व्यवहारी द्वारा विनिर्मित IMFL का शाखा अन्तरण बिहार राज्य स्थित स्वयं के डिपो में एवं 2013-14 की अवधि में झारखण्ड राज्य में स्थित स्वयं के डिपो में प्रदर्शित किया है। जांच अधिकारी द्वारा सम्पादित अग्रिम जांच में पाया गया कि व्यवहारी द्वारा मै0 बिहार स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि., पटना (बिहार) / मै0 झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि. रांची (झारखण्ड) के साथ माल IMFL की आपूर्ति के लिए लिखित में विक्रय के लिए विक्रय के समझौते (Agreement to sell) किए गये हैं एवं विक्रय के समझौते (Agreement to sell) की शर्तों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के बाहर बिहार/झारखण्ड राज्य में माल IMFL की आपूर्ति की गई है तथा विक्रय एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसरण में की गई IMFL आपूर्ति को स्टॉक ट्रांसफर प्रदर्शित किया गया है। विक्रय के समझौते के अनुसरण में व्यवहारी फर्म द्वारा विनिर्मित

202

लगातार.....2

IMFL की आपूर्ति के संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार है जबकि व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री संव्यवहारों को शाखा अन्तरण प्रदर्शित कर देय कर का अपवंचन/परिवर्जन किया जाना पाया गया। अतः जांच अधिकारी द्वारा करापवंचन का अभियोग स्थापित कर व्यवहारी फर्म के विरुद्ध के.सीएसटी अधिनियम की धारा 9 सपठित आरवेट अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु उपरोक्त अभियोग के साथ पत्रावली उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, अलवर को आयुक्त महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(ए)(10)ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/2261 दिनांक 31.03.11 की अनुपालना में स्थानान्तरण हेतु प्रेषित की गयी। उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी से पत्रावलियाँ कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित हुई।

4. जांच अधिकारी द्वारा सम्पादित जांच पर पाया गया था कि फर्म द्वारा मै0 बिहार स्टेट ब्रेवरिज कॉर्पोरेशन लि., पटना (बिहार)/ मै0 झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि. रांची (झारखण्ड) के साथ माल IMFL की आपूर्ति के लिए लिखित में विक्रय के लिए अनुबन्ध किये गये हैं। विक्रय के लिए अनुबन्ध (Agreement to sell) के अनुसरण में माल IMFL का विनिर्माण किया जाकर फर्म द्वारा मै0 बिहार स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि0, पटना (बिहार)/ मै0 झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि. रांची (झारखण्ड) को IMFL की आपूर्ति की गयी है। विक्रय के लिए अनुबन्ध (Agreement to sell) की शर्तों के अनुसरण में किए गये माल की आपूर्ति के संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार है जबकि फर्म द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री संव्यवहारों को शाखा अन्तरण प्रदर्शित कर देय कर का अपवंचन/परिवर्जन किया गया है। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि में की अन्तर्राज्यीय बिक्री संव्यवहारों को ब्रान्च ट्रांसफर प्रदर्शित कर विधि के अनुसार देय केन्द्रीय बिक्री कर संदत्त नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सीएसटी अधिनियम की धारा 9 सपठित आरवेट अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में कथन किया गया कि फर्म M/s Beam Global Spirits & Wine (India) Pvt. Ltd. आरवेट अधिनियम एवं सीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है जिसके टिन नं. 08740700340 हैं। कम्पनी भारत में बोटलिंग एवं आई.एम.एफ.एल. के वितरण का काम करती है एवं भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित डिपो में ऑपरेट करती हैं। यह एक विनिर्माता इकाई है जो कि राजस्थान में स्थित है जहां से माल का विभिन्न राज्यों में स्थित डिपो में ग्राहकों को विक्रय करने के लिये स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है। कम्पनी अपना कारोबार आई.एम.एफ.एल. में बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के डिपो के द्वारा भी करती है। बिहार में यह लिकर व्यापार मै0 बिहार स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा झारखण्ड में मै0 झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जाता है। कॉर्पोरेशन बिहार एवं झारखण्ड राज्य का पब्लिक सेक्टर उपक्रम है जो कि लिकर सोर्सिंग पोलिसी (Liquour sourcing policy) के उद्देश्य से स्थापित है तथा प्रत्यक्ष रूप से राज्य में मदिरा इत्यादि एल्कोहलिक पेय पदार्थ की बिक्री एवं प्राप्ति को संचालित करता है। कोई भी व्यवसायी अपने राज्य के सीमाक्षेत्र में मदिरा नहीं ला सकता जब तक उसे स्थानीय एक्साईज आथोरिटी की अनुमति नहीं मिल जावे। कॉर्पोरेशन ने व्यापार को संचालित करने के लिए एक पॉलिसी जो कि लिकर सोर्सिंग पोलिसी (Liquour sourcing policy) है, बनाई है। इस पॉलिसी का निर्माण विभिन्न नोटिफिकेशन जो कि बिहार और झारखण्ड के एक्साईज एक्ट एवं नियमों के तहत किया गया है इसलिये मदिरा का पूरा व्यापार इस पॉलिसी के तहत संचालित किया जाता है।

am

लगातार.....3

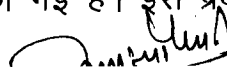
5. नोटिस में वर्णित विवादित स्टॉक ट्रांसफर की कीमत निम्नानुसार है :-

| Financial Year            | State     | Stock Transfer Amount |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 2010-11                   | Bihar     | 6694595               |
| 2011-12                   | Bihar     | 9446123               |
| 2012-13                   | Bihar     | 8218832               |
| 2013-14(up to 06.01.2014) | Jharkhand | 789569                |

6. अपीलार्थी ने जवाब में मुख्य रूप से यह कथन किया कि विवादित संव्यवहार स्टॉक ट्रांसफर हैं। कम्पनी डिपो एवं कारपोरेशन के मध्य बिक्री के लिये करार नहीं है बल्कि वितरण के लिए करार है। IMFL को बेचने का करार केवल बिहार एवं झारखण्ड राज्य के सीमा के अन्दर तक था। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 के अनुसार विक्रय और विक्रय करने का करार से आशय "माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता, माल में की सम्पत्ति, क्रेता को कीमत पर अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है। एक भागिक स्वामी और दूसरे भागिक स्वामी के बीच विक्रय की संविदा हो सकेगी। जहां कि माल में की सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अन्तरित होती है, वहां संविदा विक्रय कहलाती है, किन्तु जहां कि माल में की सम्पत्ति का अन्तरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसा शर्त के अधधीन होना है जो तत्पश्चात् पूरी की जाती है, वहां संविदा विक्रय का करार कहलाती हैं।" इस प्रकार समय-समय पर माल की मात्रा उत्पाद की मांग के ऊपर निर्भर करती है और OFS (order for supply) इस मात्रा को निर्दिष्ट करता है जो कि कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया जायेगा। इस प्रकार कम्पनी माल लिकर की आपूर्ति को मात्रा, समय और स्थान के आधार पर तय करती हैं जो कि OFS में उल्लेखित होता हैं। कम्पनी आई.एम. एफ.एल. का शाखा अंतरण बिहार और झारखण्ड में स्थित डिपो में करती है जहां से कॉरपोरेशन इसकी आपूर्ति OFS के अनुसार करता हैं। जवाब में आगे कहा गया कि कम्पनी और कॉरपोरेशन के बीच जो करार है उनके बीच माल की सम्पत्ति का कोई हस्तान्तरण नहीं होता है। यह मात्र वितरण के लिए एक समझौता है। यह बिक्री के लिए एक प्रस्ताव है जो कॉरपोरेशन द्वारा माल की आपूर्ति के लिए आदेश जारी करने पर पूरा हो जाता है। कम्पनी के बिहार व झारखण्ड डिपो में OFS के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक रखा जाता है जो नियमित रूप से कम्पनी की राजस्थान की विनिर्माण इकाई से किया जाता है। यह संचलन कॉरपोरेशन द्वारा जारी किये गये OFS से पूर्णतया स्वतंत्र है।

7. कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि लिकर सोर्सिंग पोलिसी (LSP) के बिन्दु संख्या 3.1 की अनुपालना में व्यवहारी कम्पनी व बिहार कॉरपोरेशन के मध्य करार दिनांक 17.03.2008 को निष्पादित किया है जो समय-समय पर वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिए विस्तारित किया गया है तथा वर्ष 2013-14 के लिए नवीन करार दिनांक 04.04.2013 निष्पादित किया गया है। व्यवहारी कम्पनी व झारखण्ड कॉरपोरेशन के मध्य करार दिनांक 18.04.2013 निष्पादित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह यह माना है कि क्रेता कॉरपोरेशन एवं व्यवहारी कम्पनी के मध्य माल आईएमएफएल की आपूर्ति के लिए कुछ शर्तों के अधीन लिखित करार किये गए है जिसकी शर्तों के अनुसार क्रेता कॉरपोरेशन द्वारा OFS जिसमें माल की मात्रा, कीमत, माल की कीमत वर्णित है व्यवहारी कम्पनी को दिये जाते है। व्यवहारी विक्रेता द्वारा OFS में अंकित कॉरपोरेशन के डिपो पर माल आईएमएफएल की आपूर्ति की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि करार की शर्तों के अनुसार करार माल आईएमएफएल की आपूर्ति के लिए किए गए है। उक्त करार की शर्तों के अनुसरण में माल आईएमएफएल का राजस्थान राज्य में विनिर्माण किया जाकर अन्य राज्य में माल का गमन (Movement) किया गया है। करार के अनुसार व्यवहारी द्वारा माल की आपूर्ति केवल कॉरपोरेशन को ही की गई है। इस प्रकार कॉरपोरेशन

2m

 नमस्ता

अन्तोगत्वा एकमात्र क्रेता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने माल का गमन विक्रय करार की पालना में होने के कारण उपरोक्त संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

| अपील सं.  | कर निर्धारण वर्ष | कर निर्धारण आदेश | कर        | ब्याज     | शास्ति    | योग       |
|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | 2                | 3                | 4         | 5         | 6         | 7         |
| 1272/2016 | 2010-11          | 03.05.2016       | 13,38,919 | 9,06,849  | 26,77,838 | 49,23,606 |
| 1273/2016 | 2011-12          | 03.05.2016       | 18,89,225 | 10,52,864 | 37,78,450 | 67,20,539 |
| 1274/2016 | 2012-13          | 03.05.2016       | 16,43,766 | 7,18,278  | 32,87,532 | 56,49,576 |
| 1275/2016 | 2013-14          | 03.05.2016       | 1,57,914  | 50,054    | 3,15,828  | 5,23,796  |

8. कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
9. अपील दर्ज की जाकर रिकार्ड तबल किया गया।
10. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।
11. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी राजस्थान, झारखण्ड व बिहार राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग एवं आबकारी विभाग में पंजीकृत फर्म है, जिनके द्वारा समस्त संव्यवहार नियमित घोषणा पत्रों एवं विभागीय अनुमति के आधार पर किये गये हैं। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आईएमएफएल का निर्माण किया जाकर विभिन्न राज्यों में विक्रय किया जाता है, जिसकी समस्त मॉनिटरिंग आबकारी विभाग द्वारा की जाती है एवं समस्त संव्यवहार वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी 'एफ' फॉर्म से समर्थित हैं। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किसी भी मिथ्या घोषणा से माल का विक्रय नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा निर्मित माल का नियमित प्रक्रिया के तहत राज्य के बाहर स्थित डिपो में स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A के तहत माल का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। व्यवहारी ने सर्वेक्षण के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपने समस्त बहियात एवं विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के अस्वीकार करते हुए अविधिक रूप से मांग सृजित की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।
12. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य में बियर का निर्माण कर उसकी सप्लाई बिहार स्थित फर्म मैसर्स बिहार स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना एवं झारखण्ड स्थित फर्म मैसर्स झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची को एक निश्चित करार के तहत की गयी है, जो स्पष्ट रूप से अन्तर्राज्यीय संव्यवहार की श्रेणी में आता है। व्यवहारी द्वारा आईएमएफएल का निर्माण उक्त फर्मों द्वारा निश्चित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया गया है एवं पैक की गयी बोतलों पर स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि "केवल बिहार/झारखण्ड राज्य में बिक्री हेतु"। ऐसी स्थिति में व्यवहारी द्वारा स्पष्ट रूप से करापवंचन की मंशा से अन्तर्राज्यीय विक्रय को स्टॉक ट्रांसफर बताने का प्रयास किया गया है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा इसी फर्म के वर्ष 2009-10 से 2013-14 के कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील संख्या 1229-1233/2014/अलवर में पारित निर्णय 24.11.2014 का हवाला देते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा इसी बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि की जा चुकी है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

am

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

14. हस्तगत प्रकरणों में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि व्यवहारी कम्पनी व कॉरपोरेशन के मध्य करार "विक्रय के लिये प्रस्ताव है" या "विक्रय के लिये करार" तथा इस परिप्रेक्ष्य में व्यवहारी द्वारा किये गये संव्यवहार स्टॉक ट्रांसफर माने जाये या अन्तर्राज्यीय बिक्री की श्रेणी में।

15. उपरोक्त विवादित बिन्दु के संबंध में लिकर सोर्सिंग पोलिसी के बिन्दु सं. 3 पर विचार किया जाना समीचीन है जो निम्न प्रकार है :-

3.1 Manufactures desirous of supplying liquor to the corporation (short for BSBCL) for subsequent distribution to buyers shall submit the following documents, before their offer can be considered and action initiated.

(i) Details of the organization of the manufacturer/supplier to be given in its letterhead in the format in annexure 1.

(ii) A certified copy of the license granted by the concerned Excise Commissioner/competent authority of the concerned State.

(iii) Details of executives and/or representatives to deal the Corporation to be given in its letter head as per the format in Annexure 2. And 3 respectively.

(iv) An agreement as in the format in Annexure 4 duly executed by the authorized signatory of the manufacturer/supplier in a stamp paper of denomination of Rs. 100/-

उक्त लिकर सोर्सिंग पोलिसी के अनुसरण में व्यवहारी कम्पनी व बिहार कॉरपोरेशन के मध्य करार दिनांक 17.03.2008 को निष्पादित किया है जो समय-समय पर वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिए विस्तारित किया गया है तथा वर्ष 2013-14 के लिए नवीन करार दिनांक 04.04.2013 निष्पादित किया गया है। व्यवहारी कम्पनी व झारखण्ड कॉरपोरेशन के मध्य करार दिनांक 18.04.2013 निष्पादित किया गया है। क्रेता कॉरपोरेशन एवं व्यवहारी कम्पनी के मध्य माल आईएमएफएल की आपूर्ति के लिए कुछ शर्तों के अधीन लिखित करार किये गए हैं जिसकी शर्तों के अनुसार क्रेता कॉरपोरेशन द्वारा OFS जिसमें माल की मात्रा, कीमत, माल की कीमत वर्णित है व्यवहारी कम्पनी को दिये जाते हैं। व्यवहारी विक्रेता द्वारा OFS में अंकित कॉरपोरेशन के डिपो पर माल आईएमएफएल की आपूर्ति की जाती है। विक्रय संविदा या विक्रय करार के संबंध में माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 के अनुसार विक्रय और विक्रय करने का करार से आशय-

(1) माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता, माल में की सम्पत्ति, क्रेता को कीमत पर अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है। एक भागिक स्वामी और दूसरे भागिक स्वामी के बीच विक्रय की संविदा हो सकेगी।

(2) विक्रय की संविदा आत्यान्तिक या सशर्त हो सकेगी।

(3) जहां कि माल में की सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अन्तरित होती है, वहां संविदा विक्रय कहलाती है, किन्तु जहां कि माल में की सम्पत्ति का अन्तरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसा शर्त के अध्वधीन होना है जो तत्पश्चात् पूरी की जाती है, वहां संविदा विक्रय का करार कहलाती है।

(4) विक्रय कराने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या वे शर्तें पूरी हो जाती हैं जिनके अध्वधीन माल में की सम्पत्ति अन्तरित होती है।

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यदि माल का अन्तरण आगामी समय में या किसी शर्त के अध्वधीन होता है जो तत्पश्चात् पूरी की जाती है तो वह संविदा विक्रय का करार है। हस्तगत प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार व्यवहारी कम्पनी द्वारा बिहार एवं झारखण्ड कॉरपोरेशन को आईएमएफएल की आपूर्ति की गई है जिससे अनुबंध विक्रय के लिए करार की श्रेणी में है।

2m

लगातार.....6

16. व्यवहारी कम्पनी द्वारा किये गये संव्यवहार अन्तर्राज्यीय श्रेणी में है या नहीं, इस हेतु सीएसटी अधिनियम की धारा 3 का अवलोकन करना समीचीन है :-

**3 When is a sale or purchase of goods said to take place in the course of inter-State trade or commerce-** A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of inter-State trade or commerce if the sale or purchase-

- (a) occasions the movement of goods from one State to another; or
- (b) is effected by a transfer of documents of title to the goods during their movement from one State to another.

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यदि माल का गमन (Movement) विक्रय के अनुसरण में होता है तो वह अन्तर्राज्यीय बिक्री है अर्थात् मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि माल का गमन (Movement) प्रारम्भ होने का कारण क्या है। यदि किसी निर्धारित पक्ष से माल की बिक्री के अनुसरण में माल का गमन प्रारम्भ होता है तो वह संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री की श्रेणी में है। हस्तगत प्रकरणों में करार की शर्तों के अनुसार करार बिहार/झारखण्ड कॉरपोरेशन को माल आईएमएफएल की आपूर्ति के लिए किए गए हैं। उक्त करार की शर्तों के अनुसरण में माल आईएमएफएल का राजस्थान राज्य में विनिर्माण किया जाकर अन्य राज्य में माल का गमन (Movement) किया गया है। करार के अनुसार व्यवहारी द्वारा माल की आपूर्ति केवल कॉरपोरेशन को ही की गई है। इस प्रकार कॉरपोरेशन अन्तोगत्वा एकमात्र क्रेता है। इस प्रकार माल का गमन विक्रय करार की पालना में होने के कारण उपरोक्त संव्यवहार अन्तर्राज्यीय बिक्री की श्रेणी में है।

17. हस्तगत प्रकरणों में व्यवहारी अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा निष्पादित अनुबंध "विक्रय के लिए करार नहीं है बल्कि विक्रय के लिए प्रस्ताव" है, विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में The Indian Contract Act, 1872 की धारा 2 के संबंधित भागों का उल्लेख करना समीचीन है :-

## **2.Interpretation - clause**

In this Act the following words and expressions are used in the following senses, unless contrary intention appears from the context:

- (a) **When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal;**
- (b) **When a person to whom the proposal is made, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise;**
- (c) **The person making the proposal is called the "promisor", and the person accepting the proposal is called "promisee",**
- (d) **When, at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing, something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise;**
- (e) **Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement;**
- (f) **Promises which form the consideration or part of the consideration for each other, are called reciprocal promises;**
- (g) **An agreement not enforceable by law is said to be void;**
- (h) **An agreement enforceable by law is a contract;**
- (i) **An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract;**
- (j) **A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable.**

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार "प्रस्ताव" एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई कार्य करने या न करने के संबंध में इच्छा प्रस्तुत करना है। ज्योंही दूसरा पक्ष इससे सहमत हो जाता है तो वह प्रस्ताव "Promise" बन जाता है। जब दोनों पक्ष किसी प्रतिफल पर Promise को पूर्ण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह "Promise", "करार" बन जाता है। हस्तगत प्रकरणों में व्यवहारी कम्पनी व बिहार/झारखण्ड कॉरपोरेशन के मध्य आईएमएफएल आपूर्ति करने का Promise हुआ है जो करार की श्रेणी में है न कि प्रस्ताव की श्रेणी में।

18. अपील संख्या 1229-1233/2014/ अलवर मैसर्स युनाईटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, भिवाड़ी बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 24.11.2014 पारित करते हुए अवधारित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से अन्तर्राज्यीय विक्रय को स्टॉक ट्रांसफर दर्शाया गया है, अतः आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि की गयी है। राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"After hearing the counsel for both the parties, studying judgments of the Hon'ble Courts (cited supra) and the record placed before us, we set out in the matter as given herein under :

At the outset, we agree with counsel for the Revenue that show cause notice issued was a detailed one and reply and submissions were properly given consideration, and proper opportunity of even personal hearing was given and speaking orders were passed.

Amidst rival contentions of the counsel, what transpires is that all essential conditions of section 3(a) of the CST Act are witnessable in the present case. On the authority of M/s TELCO Vs Assistant Commissioner, (supra) they could be deduced from Agreement to sale (supply) of beer between BSBCL and the appellants, necessitating and occasioning movement of beer from appellants manufacturing units in Rajasthan to Bihar on the premise of same transaction.

The interstate movement of beer in instant cases was preceded by Agreement to sale and interstate sale related to it was inextricably interwoven with corresponding beer movement from district Alwar, Rajasthan to Patna, Bihar. The facts here are distinguishable from those of Central Distilleries and Breweries (supra), on the authority of case applicable in present scenario, that is M/s Indian Oil Corpn. Ltd., (supra). It is manifest that interstate movement of beer from Alwar to Patna did not break there but after a brief interval continued to finally terminate at different BSBCL depots in Bihar. It did not rupture the inextricate relationship between the movement of goods and sale, because sale could only be made to BSBCL by the sole seller, appellant manufactures. With no third party involvement in the whole scheme of sales, such a brief stoppage of movement of beer at Patna at appellants depot at Patna for a while did not impact the nature of interstate sale because at the most it was a transit halt of the goods in question.

The respondent Assessing Authorities have made out a case that in relation to the movement of beer stocks round the year from the appellant assesses' manufacturing units situate in district Alwar of Rajasthan to their branch offices at Patna and Ranchi was not result of bare stock transfers of beer but rather sales thereof to the various retail outlets of the BSBCL (or, JSBCL ) spread across the State of Bihar ( or, Jharkhand ) made in course of the inter-State trade and commerce, between appellants and BSBCL.

The facts of present cases require analysis in the light of the provisions of the section 3 of the CST Act, 1956. It is a simple fact that Inter State sale or purchase is carved out of and separated from inside sales or purchases for the purpose of situs of taxation. It is to be explored whether the movement of beer from the State of Rajasthan to the State of Bihar (or, Jharkhand) was the result of a covenant or an incident of the contract of sale entered to between the authorized representative of appellant company and Bihar State Beverage Corporation Limited, if it were so, the sale was an inter-State sale.

am



We may have a look at the provisions of the LSP which are contextually relevant in the present case and reproduced as under :

1. The clause 3.1 of the LSP stipulates that **manufacturers desirous of supplying liquor to the BSBCCL for subsequent supply to buyers** shall submit certain documents, before their offer can be considered and action initiated, one of them being (iv) is, as follows:

*“an agreement as in the format in Annexure 4 duly executed by the authorized signatory of the manufacturer/ supplier in a stamp paper of denomination of Rs.100/-*

2. Clause 4.1 of the LSP says that labels of brands proposed to be supplied / marketed in Bihar by a manufacturer / supplier located in or outside the state have to be approved by the Excise Commissioner, Bihar, Patna. Such an approval shall be obtained by the manufacturer / supplier and submitted to the Corporation.

3. Clause 4.2 of the LSP lays down that manufacturers / suppliers located outside the state shall submit a copy of the permission for the manufacture of the brands proposed to be supplied, approval for labels as granted by the competent excise authorities of that state and the authorization for exporting from that state to Bihar.

4. Clause 5 of the LSP says that a statement for each brand of FMFL/IMFL/BEER/WINE indicating information for label registration of a brand of FMFL/IMFL/BEER/WINE shall be submitted .

5. Clause 5.5 (A) (i) of the LSP determines that the price, which will be offered now, shall be valid, at the option of the offerer.

6. Clause 5.5(ii) of the LSP says that In respect of brands manufactured in Bihar or imported from outside the state the corporation is required to declare the price for sale to retailer and the maximum retail selling price of such products. Manufacturer shall quote the landed price.

7. Clause 5(B) stipulates that the landed prices quoted should be F O R destination. The manufacturer / supplier has to incur the entire expenditure till the consignment is received and stacked at the destination i.e., designated depots of the Corporation or any other location within Bihar, as specified in the permit. Unloading of the goods at the depots shall be the responsibility of the manufacturer / supplier located both inside and outside the State of Bihar, the consignments have to be dispatched under valid permit issued in the name of the M/s Bihar Beverages Corporation Ltd., Patna by the competent authority.

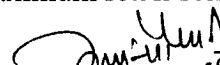
8. In respect of stocks of FMFL/IMFL/BEER/WINE, imported from outside the State or procured from within the State, all the bottles are to be affixed with holograms if it is supplied by the Excise Commissioner, Govt. of Bihar.

9. Clause 5(C) The price quoted shall be uniform irrespective of the location of the destination within Bihar.

10. Clause 5.6 says that (a) The offerer shall quote only for the brands for which the labels are approved by the Excise Commissioner, Govt. of Bihar, as on the date of submission of offer.

11. Clause 5.8 of the LSP cautions manufacturers to note that they are required to work out the Landed cost and the maximum retail selling price, taking

am

 .समाप्त



due note of the provisions of the different notifications with respect to duties, fees issued by the Excise Department or the Excise Commissioner, Government of Bihar under the Bihar Excise Act and rules framed there under.

12. Clause 5.9 of the LSP fixes the margin of Corporation to be calculated in such a way that it is not more than 5% of the M.R.P. Likewise retailers margin will also be calculated in such a way that it is not more than 15% of the MRP.

13. Clause 5.16 of the LSP declares there shall be a **Purchase Committee** duly constituted by Govt. of Bihar which will fix the price of 'brands quoted.

14. Clause Rule 6.1 of the LSP provides for the mechanism of issuance of OFS : Manufacturers / Supplies to the Corporation shall be based on the OFS issued by it. The corporation shall issue OFS based on the stock requirement of depots after duly considering the quantity held, the sales trend and requests of the manufacture / supplier, if any. To facilitate the process, the manufacture / supplier may indicate the requirement of its brands, and pack sizes in various depots. However, the corporation reserves its right to decide the quantity for which OFS can be issued.

15. Clause Rule 6.2 of the LSP holds that the Quantity to be procured from time to time shall depend upon the demand for the product. Further, the corporation shall not be under any legal compulsion to procure all or any brands produced by a particular manufacture / supplier, **simply because they have signed this Agreement and have made an offer.**

16. Clause Rule 6.4 of the LSP declares that two copies of the OFS will be issued for the exact quantity that the supplier / manufacture proposes to transport. It is, therefore, imperative that manufacture / supplier indicate their dispatch plan for issue of OFS. The OFS shall be signed by either of the authorized signatories of the Corporation.

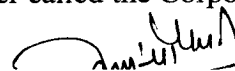
17. Clause Rule 6.7 of the LSP sets out that In respect of supplies from within state or outside the State, the manufacture / supplier or their authorized representatives shall, after the issue of OFS , deposit the Import Fee, Excise Duty and other applicable duties or fees for their respective brands with the Excise Department and obtain required transport permit to ensure delivery.

18. Clause2 GENERAL D.Landed Price defines Landed Price at BSBCIL ware house means all inclusive of EDP, Freight, handling, Insurance, State/Central levies, duties, fees & excise duty and Commercial Tax.

A. In this regard, It is imperative to go through the agreement entered into between the appellant and the BSBCL under the terms and conditions of the LSP as described in its Circular no.675/BSBCL, dated 12.03.2008 ( extended for the relevant years : 2009-10 ,2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 ).\_B. At the background of above, It is apparent that the appellant **manufacturers who were desirous of supplying liquor to the BSBCL for subsequent supply to buyers** in reference to the aforesaid Clause 3.1 of the LSP submitted certain documents, before their offer was considered and action initiated by ESBCL. We find that in terms of Clause 3.1 (iv) of the LSP, an Agreement was struck between the two parties to the issue, the BSBCL and the appellant company, the introductory part of which is reproduced as under:

“This Agreement made at Patna...of 2008 between **the Bihar State Beverage Corporation Limited** (hereinafter called the Corporation) having its

am

 लगातार

head office at....Patna represented by .... which term shall mean and include its executors,.....etc.,of the ONE PART AND M/s Shivalik Industres Limited represented by Shri L K Tiwari (hereinafter called manufacturer / supplier , the term including supplier) which term, unless repugnant to the context, shall mean and include its executors, administrators, successors in interest, assigns, ets., of the OTHER PART

In all matters connected with and in relation to all matters of liquor supplies to the Corporation for the year 2008-09 in the territory of the State of Bihar and witnessed ", amongst other stipulations, under sub clause 1 of clause 1 "that the quantity of liquor to be procured and distributed shall be determined by the Corporation from time to time, keeping in view the demand for liquor manufactured / supplied by the manufacturer / supplier "

4. This Agreement entered into between the BSBCL and the appellant companies having manufacturing units in Alwar, Rajasthan and the branches at Patna in Bihar and Ranchi in Jharkhand is the *cause celebre* in the present context, enabling appellants' beer sales in the State of Bihar (or, Jharkhand) through the instrument called 'Order for Supply ' issued by the BSBCL to the appellant's branch at Patna in Bihar,

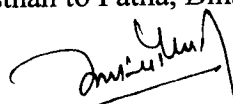
5. The appellant assesses hold the above Agreement not as an Agreement for Sale of beer but an Agreement for distribution of beer in the State of Bihar.

6. Agreement to Sale or contract to sale, or in opinion of the appellants an Agreement to Distribution was implemented when OFS was issued by BSBCL, leading to import of beer from the manufacturing units of the appellant assesses and supply of which was as usual shown as having been stock transferred to Patna (or, Ranchi) branch of the appellants which in turn sold beer to the designated Depots of the BSBCL located in various towns of Bihar. The plea of the appellants that the beer by way of stock transfer, independent of any order, was continually transferred to the Patna branch of the appellants, where it was unloaded and stacked in the godown of the appellant company at Patna. When an OFS was issued by BSBCL for supply of beer to any of its depots located in any of the towns or city of Bihar, they raised the VAT invoice for such a sale and arranged transport for carrying beer to the designated depot of the BSBCL. This way, the sale of beer in Bihar was a local sale, and the bogey of inter-State sale raised by the respondents was a wild goose chase.

In the background of the above facts, it is found that the respondent Assessing Authority was right in assuming jurisdiction under section 25 of the RVAT Act, because he had sufficient reason to believe that the appellant had avoided paying CST on impugned transactions. On the authority of finding in case of M/s Hyderabad Engineering Vs State of Andhra Pradesh (supra), the respondent Assessing Authority rightly considered that it had not taken advantage of the presumption under Section 3(a) of the CST Act, but had rather made a positive case of inter-State sale in the course of Interstate trade and commerce that rendered declaration in Form "F" under section 6A irrelevant.

At the back drop of aforesaid analysis of facts and legal position, it is decided that impugned transactions were verily interstate sales under Section 3(a) of the CST Act, in which aforesaid Agreement to sale executed between BSBCL and appellants acted as contract to sale and caused interstate sales that occasioned movement of beer from district Alwar, Rajasthan to Patna, Bihar.

20/



लगातार.....11

As regards, the imposition of interest under section 55 of the RVAT Act on the impugned interstate sale transactions, the learned counsel of the appellants had argued that interest was payable on the tax due in the books and returns and not the tax due as per assessment orders, whereas counsel for the respondent said it was due when leviable and payable. We find that the assessing authority levied tax on the impugned transactions which made the interest thereon payable. The assessing authority has correctly imposed interest.

As regards penalty imposed under Section 61 of the RVAT Act it could be levied in any of the following circumstances :

- (a) Concealment of particulars from any return; or
- (b) Deliberately furnishing inaccurate particulars in any return; or
- (c) Concealment of any transaction of sale or purchase from accounts, registers or documents; or
- (d) Avoidance or evading tax in any other manner

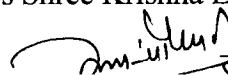
It was argued that the appellants had no intention to evade tax on the impugned transactions shown as stock transfers which were in reality transactions of interstate sales. Of course, it is an undisputed fact that impugned stock transfer transactions were declared and disclosed by the Appellant in the returns furnished with the VAT Authorities and further the disputed stock transfer transactions were well recorded and accounted for in the books of accounts maintained by the appellant companies.

The learned counsel for M/s Carlsberg India (P)Ltd, Mr. Laxamikumaran had argued that the appellant was under a bonafide belief that the transactions in question were a stock transfer transaction: the bonafide of the Appellant was based on the ratio decendi of decisions and case laws cited above, specifically, the case of Central Distilleries & Breaweries (Cited supra), wherein under similar facts and circumstances the Hon'ble Allahabad High Court was said to have held transactions identical to the Appellants to be in the nature of stock transfer and not inter-state sales.

The learned counsel for M/s Mount Shivalik Industries Ltd, Mr. Alkesh Sharma, and Mr. Vivek Singhal for M/s United Breweries had emphasized that stock transfers of the appellant were converted into interstate sales by the Assessing Authority merely on presumptions and conjectures, based on a change of opinion inasmuch as not a single transaction of alleged sale or purchase had been detected by the Assessing Authority and which led to double taxation on the same goods. Relying upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of M/s Shree Krishna Electricals vs State of Tamil Nadu (supra), they wanted that unjust levy of penalty under section 61 of 2003 Act be set aside. They had argued that Hon'ble Apex Court had held in the aforesaid case that "so far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's books of accounts. Where certain items are not included in the turn over, are disclosed in the dealers own books of accounts and the Assessing Authorities include these items in the dealers turnover disallowing exemption penalty cannot be levied", and submitted on this account that in their case all the transactions were appearing in the appellant's books of accounts and the deduction in respect of such branch transfers had been allowed, therefore there was no ground for imposing penalty in such cases.

In the humble opinion of the Bench, the facts of the present case differ from the facts prevailing in the aforesaid case of M/s Shree Krishna Electricals, wherein



 लगातार.....12

the assessee had not included certain items in the turnover but they were found entered in his books of accounts. Here, it is a case of the malafide intention of the appellants in consciously depriving the state of Rajasthan of their due tax revenue under Central Sales Tax by concealing the nature of inter-state transactions under the garb of stock transfers made from the State of Rajasthan to the State of Bihar (or, Jharkhand). The facts of the present cases are distinguishable from those of the aforesaid cases cited above. In the present context, they are not based on commodity and turnover but on nature of sales which has been deliberately misrepresented in the books of accounts and disclosed in returns as branch transfer. Instead of as interstate sales.

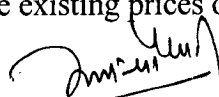
Going by the facts and legal pronouncements as aforesaid hereinabove, we have come to the conclusion that agreement for supply of Beer to the BSBCL by the appellants was an agreement to sale which was duly executed between the BSBCL and the appellant companies having their manufacturing units in district Alwar Rajasthan and branch offices in Patna in year 2008, which inter alia, had agreed upon the terms and conditions in respect of the fix Landed Price for supply and delivery of beer by the manufacturer to destinations of the designated warehouses in Bihar. The BSBCL in its liquor sourcing policy clearly defines the Landed Price as "Landed Price at BSBCL warehouse means all inclusive of EDP, Freight handling Insurance, State / Central levies, duties, fees & excise duty and Commercial Tax". The wording of Landed Price is quite revealing inasmuch as tax provisions are the concerned, it uses the word commercial tax which includes both state VAT & Central Sales Tax, the relevant document has not excluded Central Sales Tax from the ambit of the Landed Price. Nor has it confined itself to the local VAT in the state of Bihar. Appellant companies were asked to offer the firm prices for their liquor products on the basis of the Landed Price which included local Bihar VAT @50% on the sale of liquor products including beer to the designated depots of BSBCL in territories of Bihar. None debarred them from the inclusion of due CST applicable on such interstate sales of beer from their units in Alwar to the designated depots of BSBCL. Mere interruption of sales during the course of transit at their branches in Patna could not divert the nature of interstate sale effected between the appellants and BSBCL. So far as the liability to pay 50% VAT on local sales in Bihar is concerned it could have been taken care of by their inside sale mechanism in the state of Bihar on which the Board would not like to dwell upon as it would amount to exceeding its jurisdiction.

The charge that a single stock transaction has been converted into interstate transaction would lead to double taxation on the same product because the appellant had deposited VAT @50% on such transaction as local sale in state of Bihar is not correct proposition because the appellant is trying to coalesce the interstate sale from Bihar to Rajasthan into subsequent local sale in the state of Bihar in one transaction which in fact were two different sale transactions: one, interstate sale of beer between the appellant assessee and BSBCL and second local sale in the state of Bihar regarding which the respondent Revenue had no right to interfere in or advise on inasmuch as workability and applicability of local VAT on subsequent sale in other state was concerned. It was exclusively in the domain of appellant and BSBCL.

It would be worthwhile to go through Clause 5.7, Clause 5.8 and Clause 5.9 of the Liquor Sourcing Policy:

Clause 5.7 "The offerer shall quote the prices for their products on competitive basis keeping in view the existing prices of similar brands".

2m



लगातार.....13

Clause 5.8 “Manufacturers may please note that they are required to work out the Landed cost and the maximum retail selling price, taking due note of the provisions of the different notifications with respect to duties / fees issued by Government of Bihar (Excise Department) / Excise Commissioner under Bihar Excise Act and rules framed there under. The corporation reserves the right to decide the extent of incidental overhead to be allowed for Bihar. Incidental overhead will include all other fees / levies / cost applicable other than the EDP”.

Clause 5.9 “The margin of Corporation shall be calculated in such a way that it is not more than 5% of the M.R.P. Likewise retailers margin will also be calculated in such a way that it is not more than 15% of the MRP”.

From the analysis of above Clauses emerges a picture that the appellants were allowed to fix Landed Cost and maximum selling price in which they could have included CST as well, apart from making provision for local VAT in Bihar which the appellants may have already done, as component of price quoted. However, Clause 5.9 in that case might have curtailed their profit margins. But that is not a point in consideration before us from the view point of applicability of Incidence of Central Sales Tax on the impugned transactions. In conclusion it comes about that the supply of beer to the BSBCL by the appellants from the initial stage was a premeditated deliberate exercise to excise CST on the inter-State sale transactions by the appellants in flagrant violation of conditions as exhibited in the aforesaid Agreement, implications of which were well known to the appellants right from the beginning when such interstate sales were deliberately disclosed as branch transfer transactions by them. In fact, the ratio decidendi was in favour of Assessing Authorities in respect of imposition of penalty under section 61 of the RVAT Act in the impugned assessment orders and is, therefore, upheld.

On the basis of aforesaid analysis of factual and legal matrix of the impugned assessment orders, the bench upholds tax, interest and penalty therein and dismisses the aforesaid appeals.

19. माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय से संबंधित अपीलों में भी अपलार्थी व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में मै0 बिहार स्टेट ब्रेवरिज कॉर्पोरेशन लि., पटना (बिहार) / मै0 झारखण्ड स्टेट ब्रेवरिज कॉर्पोरेशन लि. रांची (झारखण्ड) के साथ लिकर सोर्सिंग पोलिसी के अन्तर्गत अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीयर / लिकर की आपूर्ति की गई है तथा ऐसी आपूर्ति को माननीय खण्डपीठ ने अन्तर्राज्यीय संव्यवहार माना है तथा कर, ब्याज व शास्ति को विधिसम्मत माना है। हस्तगत प्रकरणों के तथ्य भी इन्हीं अपीलों के समान हैं जिससे यह न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरणों में पूर्णरूपेण लागू होता है।

20. माननीय खण्डपीठ के उक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण में अन्यथा किसी विवेचन की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों अस्वीकार की जाती हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये चारों आदेश दिनांक 03.05.2016 की पुष्टि की जाती है।

21. निर्णय सुनाया गया।

(नरेश्वर)  
सदस्य

(राजीव चौधरी)  
सदस्य